राज्य के 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लांच कर 11,250 मकान बनाएंगे : अरोड़ा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। हाऊसिंग बोर्ड राज्य के 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लांच करेगा। जयपुर के प्रतापनगर में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना लाई जायेगी। इन सभी योजनाओं का शुभारंभ एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा करवाया जायेगा। यह निर्णय बुधवार को मंडल अध्यक्ष भास्कर ए.सावंत और आयुक्त पवन अरोड़ा की मौजूदगी में आयोजित बैठक में हुआ। अरोड़ा ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का सपना है कि उसका अपना आशियाना हो। इसलिए हर वर्ग की जरूरत के हिसाब से उचित कीमत पर मकान मुहैया करवाये जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के लिए जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर-26 में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना लांच की जाएगी। इसमें प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार कुल कुल 674 फ्लैट्स बनाये जाएंगे। यहां 10 लाख 90 हजार रूपये में 632 वर्गफीट में निर्मित 2 बीचएचके फ्लैट, 15 लाख 70 हजार रूपये में 882 वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित 2 बीचएचके फ्लैट और 21 लाख रूपये में 1097 वर्ग फीट में निर्मित 3 बीचएचके फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में पूर्व में लांच की गई मुख्यमंत्री राज्य सहायक कर्मचारी योजना के आवेदकों को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना के आस-पास स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध है।

आवासन मंडल के अध्यक्ष भास्कर ए.सावंत और आयुक्त पवन अरोड़ा की मौजूदगी में बुधवार को प्रदेश में प्रस्तावित आवास योजनाओं को लेकर बैठक हुई। इस दौरान मुख्य नगर नियोजक आर.के.बिजयवर्गीय, मुख्य अभियंता के.सी. मीना, जी.एस. बाघेला, अतिरिक्त नगर नियोजक अनिल माथुर मौजूद थे।

- जयपुर के सिरोली, वाटिका, महला, शाहपुरा, उदयपुर के दक्षिण विस्तार व देवारी, सूरतगढ़ , निवाई, आबूरोड़, नसीराबाद, किशनगढ़ डूंगरपुर व बांसवाड़ा में लांच होगी स्कीम
- सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतापनगर-सेक्टर 26 में 2 व 3 बीएचके साइज के फ्लैट्स बनेंगे

आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि हाऊसिंग बोर्ड जल्द ही 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लांच की जाएंगी। यह योजनाएं जयपुर के सिरोली, वाटिका, महला, शाहपुरा, उदयपुर के दक्षिण विस्तार एवं देवारी, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ , टोंक के निवाई, सिरोही के आबूरोड़, अजमेर के नसीराबाद, किशनगढ़ , डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होंगी। इन योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब व उच्च आय वर्ग के लिए कुल 11 हजार 250 आवास उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत देय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष के इतिहास में इतनी योजनाएं एक साथ कभी भी लांच नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि '10 प्रतिशत दीजिये, गृह प्रवेश कीजिये' योजना में किस्तों पर जीएसटी लगने के संबंध में भ्रम की स्थिति थी। इस संबंध में जीएसटी विशेषज्ञों से चर्चा कर ली गई है, यह चूंकि पूर्व निर्मित मकान है इसलिये जीएसटी न तो किस्तों पर और न ही ईएमडी पर लगेगा, अब यह मकान आमजन को और भी सस्ते उपलब्ध होंगे।

मंडल अध्यक्ष भास्कर ए. सांवत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में 27 प्रकरणों पर विचार किया गया। इस बैठक में मुख्य नगर नियोजक आर.के.बिजयवर्गीय, मुख्य अभियंता के.सी. मीना, जी.एस. बाघेला, अतिरिक्त नगर नियोजक अनिल माथुर, उप नगर नियोजक संत सरन समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।